**खंडवा-बुरहानपुर राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना**

108. **श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदौर-धूलिया तथा खंडवा बरहानपुर राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के बारे में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है अथवा क्या केन्द्रीय सरकार इन राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिये स्वयं कोई कार्यवाही कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीता राम केसरी) :** (क) और (ख). मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 1980-85 की योजना में जिन मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव दिया है उनमें अन्य मार्गों के साथ-साथ खंडवा-बरहानपुर मार्ग भी है । लेकिन आर्थिक कठिनाई और अन्य आवश्यक कार्यों के कारण राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं हो सका है । वह स्थिति अब भी बनी हुई है और यह बात मध्य प्रदेश के साथ-साथ सभी अन्य राज्यों पर भी लागू होती है ।

**प्राथमिक स्कूलों की संख्या मे वृद्धि**

109. **श्रीमती कृष्णा साही :**
**श्री राम स्वरूप राम:**

क्या शिक्षा और संस्कृत मंत्री निम्न जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व में कुल 72 करोड़ तथा 30 लाख निरक्षरों में से 42 करोड़ तथा 40 लाख भारत में ही हैं;

(ख) क्या यह सच है कि शिक्षा के लिये कुल बजट आबंटन में से 22 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किया जाता है;

(ग) क्या यह भी सच है कि देश में लगभग 6 लाख गांवों में से प्राथमिक स्कूलों की संख्या 44 हजार है और उक्त स्कूलों में से 40 प्रतिशत स्कूलों में एक-एक अध्यापक है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा निरक्षर लोगों की संख्या कम करने तथा देश में प्राथमिक स्कूलों की संख्या में वृद्धि करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल):** (क) निरक्षर आबादी के नवीनतम अनुमानित आंकड़े निम्नलिखित हैं :

(1) विश्व : 81.40 करोड़, आयु 15 वर्ष तथा इससे ऊपर (1980, यूनेस्को अनुमान);

(2) भारत 1981 की जनगणना के अनुसार निरक्षर आबादी के आयु वर्ग के ब्यौरे अभी उपलब्ध नहीं हैं । तथापि, 1971 की जनगणना के अनुसार भारत में निरक्षर लोगों की संख्या 30.72 करोड़ थी, इसमें 15 तथा इससे ऊपर के आयु-वर्ग के 20.95 करोड़ तथा 5-15 आयु-वर्ग के 9.77 करोड़ भी शामिल हैं ।

(ख) 1981-82 के बजट उपबन्धों के अनुसार, प्रारम्भिक शिक्षा के लिए बजट बद्ध राशि राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के कुल शिक्षा बजट की 47.5 प्रतिशत थी।

(ग) चौथे अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण (सन्दर्भ तारीख 30-9-78) के अनुसार 4,74,636 प्राथमिक स्कूल थे । जिनमें से 1,64,931 अथवा 34.7 प्रतिशत एकल-शिक्षक स्कूल थे ।

(घ) अनुच्छेद 45 में निर्धारित संवैधानिक लक्ष्य के अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण को प्रौढ़ शिक्षा के इसके प्रशंसात्मक कार्यक्रम सहित छठी योजना (1980-85 के न्यूनतम कार्यक्रम में शामिल

कर लिया गया है । छठी योजना के इन कार्यक्रम का उद्देश्य प्रारम्भिक शिक्षा (कक्षा 1-8) में 6-14 आयु वर्ग के बच्चों का शत-प्रतिशत दाखिला तथा 1989-90 तक 15-35 आयु-वर्ग के सभी व्यक्तियों में निरक्षरता का उन्मूलन करना है । ये नए 20 सूत्री कार्यक्रम का भी हिस्सा है ।

छठी योजना के अन्तर्गत, 300 अथवा अधिक आबादी वाली 6.95 प्रतिशत व्यवहार्य बस्तियों के सम्बन्ध में एक किलो-मीटर के अन्दर प्राथमिक स्कूली शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करने के प्रयास किये जा रहे हैं । चौथे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार 93.05 प्रतिशत ऐसी बस्तियों में प्राथमिक स्कूली शिक्षा की सुविधाएं पहले ही प्रदान की जा चुकी हैं ।

**Scheme of convesion of narrow gauge Railway lines into broad gauge.**

110. SHRI CHANDRAJIT YADAV: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the Railway Ministry, in consultation with the Planning Commission, has drawn up a comprehensive scheme to convert all narrow gague railway lines into broad gauge;

(b) whether the Railway Ministry is drawing a long term scheme for the conversion of all narrow gauge lines into broad gauge so that the Planning Commission and the Railway Ministry are able to provide funds within next two Five Year Plans for such conversions; and

(c) if so, the facts thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) to (c). Basically Gauge Conversion proposals are considered only when it is discovered that the traffic likely to develop in future cannot be handled on the existing system. Considered from this angle Narrow Gauge (N.G.) sections are comparatively much less important to recommend themselves for conversion into Broad Gauge (B.G.). Further-more, for want of resources even some of the busy Metre Gauge (M.G.) routes could not be accommodated for conversion into B.G. No scheme is, therefore, proposed at present, nor funds asked for conversion of N.G. into B.G.

**Abolition of public School system**

111. SHRI CHANDRAJIT YADAV : Will the Minister of EDUCATION AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are considering to have a uniformity in Educational System throughout the country by abolishing public schools and raising the standard of education from primary to the University level;

(b) whether Government have invited the views of the State Governments in this regard, if not, whether Government propose to call the State Education Ministers' Conference alongwith the eminent educationists; and

(c) whether Government are aware that after studies in junior high schools the emphasis would be for education at all levels?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF EDUCATION AND CULTURE AND SOCIAL WELFARE (SHRIMATI SHEILA KAUL): (a) to (c). The 10 2 system of school education has been recommended *inter alia* with the objective of having a uniform system of education throughout the country. Various aspects of this system had been discussed in various national forums, including the Conferences of Education Ministers of States and Union Territories from time to time. However, the concept of standard of education is very comprehensive. Taken in its totality, there has been a definite thrust towards upgrading standards of education The question of abolition of public schools was examined sometime back and the legal opinion tendered to the Government was to the effect that any action to abolish public schools would be violative of constitutional provisions.